देश के लिए विश्व कप जीतना लक्ष्य

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

भुवन बाम की नयी फिल्म की शूटिंग शुरू

Page-05

पटना NEET छात्रा मौत मामला:

CBI ने संभाली जांच

पटना, टीवी भारतवर्ष

पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अपने हाथ में ले ली है। CBI ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज करते हुए केस नंबर 7S/26 आवंटित किया है।बताया जा रहा है कि इस मामले की CBI जांच की मांग लगातार उठ रही थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था। बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से इस मामले की CBI जांच कराने का औपचारिक अनुरोध किया था।राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद CBI ने आधिकारिक रूप से केस टेकओवर कर लिया है। इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सम्राट चौधरी ने साझा की थी।सूत्रों के अनुसार, बिहार CBI के अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि CBI अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी और अब तक की पुलिस जांच के दस्तावेजों की समीक्षा भी करेगी।इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। वहीं, पूरे राज्य की निगाहें अब CBI की जांच पर टिकी हैं।

कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा को जमानत,

पुलिस की 14 दिन की रिमांड याचिका नामंजूर

कानपुर, टीवी भारतवर्ष

कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कांड में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा दाखिल की गई 14 दिनों की रिमांड अर्जी को भी खारिज कर दिया गया।सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवम मिश्रा से विस्तृत पूछताछ जरूरी है। पुलिस का तर्क था कि घटना से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की जांच अभी बाकी है और रिमांड मिलने पर साक्ष्यों को और मजबूत किया जा सकता है। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस के पास पर्याप्त समय था और रिमांड की कोई ठोस आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग को अस्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर ली।गौरतलब है कि लैंबॉर्गिनी कांड सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को हिरासत में लिया था। मामले को लेकर शहर में काफी चर्चा रही और सोशल मीडिया पर भी इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।हालांकि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जांच समाप्त हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहीं, पुलिस का कहना है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। आने वाले दिनों में पुलिस आगे की विवेचना और साक्ष्य संकलन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी जल्द तय किए जाने की संभावना है।

पुणे में बंगाली प्रवासी मजदूर की हत्या पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा—

'भाषा और पहचान के आधार पर घृणा अपराध'

कोलकाता, टीवी भारतवर्ष

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के पुणे में काम कर रहे पुरुलिया निवासी 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की हत्या पर गहरा सदमा और आक्रोश व्यक्त किया है। गुरुवार को जारी बयान में उन्होंने इस घटना को 'घृणा अपराध' करार देते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित को उसकी भाषा और पहचान के कारण निशाना बनाया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि सुखेन महतो पर हमला ऐसे माहौल में हुआ है, जहां विदेशी-विरोधी या बाहरी लोगों के खिलाफ भावना को उकसाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "विदेशी-विरोधी भावना को हथियार बनाकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय है।"उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इसे कानून-व्यवस्था की विफलता बताया है और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं, स्थानीय प्रशासन की ओर से जांच जारी होने की जानकारी दी गई है।

उत्तर कोरिया में सत्ता का नया संकेत:

किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ को उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के शासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हाल ही में अपने संसद के संवाददाताओं को जानकारी दी है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ को अब औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम संकेत देता है कि उत्तर कोरिया की सत्ता में चारवीं पीढ़ी के लिए परिवारिक राजशाही का सिलसिला जारी रह सकता है। सूत्रों के अनुसार, जू ऐ ने पिछले कुछ समय में अनेक महत्वपूर्ण सरकारी एवं सैन्य कार्यक्रमों में भाग लिया है और उसके सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के तरीके को लेकर विश्लेषकों और खुफिया एजेंसियों की निगाहें लगातार बनी रही हैं। खासकर उसने अपने पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन जैसे प्रतिष्ठित स्थल का दौरा किया, जहां उत्तर कोरिया के संस्थापक और पूर्व नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है — इस कदम को एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी का मानना है कि अब वह केवल उत्तराधिकारी के संभावित उम्मीदवार के रूप में ही नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए जाने के चरण में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने यह बातें पार्लियामेंट की इंटेलिजेंस कमिटी में साझा कीं, जिनका उद्देश्य भविष्य के उत्तराधिकार के तरीकों को समझना है। जू ऐ की सक्रिय मौजूदगी और कुछ नीतिगत मामलों पर उसके विचार सामने आने जैसे संकेतों से लगता है कि उसे सत्ता की अगली कतार में लाया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना को नई शक्ति:

मोदी सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त राफेल जेट्स खरीदने की मंजूरी दी

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम रक्षा निर्णय लिया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फ्रांस से अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इससे भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और हवाई श्रेष्ठता को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।सरकार ने बताया कि यह कदम उदार रणनीतिक परिस्थितियों और रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। राफेल विमान अपने उन्नत लड़ाकू क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बहुआयामी मिशन क्षमता के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय वायुसेना ने पहले ही राफेल विमानों को अपनाया है और इसके संचालन से प्रशिक्षित पायलटों तथा रखरखाव कर्मियों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ दी हैं।पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली और टेक्नोलॉजी में निरंतर निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य न केवल सीमाओं की रक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने में एक मजबूत भूमिका निभाना भी है। राफेल जैसे एविएशन प्लेटफॉर्म भारत को बहुआयामी अभियानों में अधिक सक्षम बनाएंगे।सरकारी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नई खरीद की प्रक्रिया लंबी रणनीतिक योजना का हिस्सा है और यह भारत-फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करेगी। फ्रांस एक पुराने और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है, जिसने भारत को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा एवं औद्योगिक साझेदारी को और बल मिलेगा।

रूस में इंस्टाग्राम और फेसबुक के बाद WhatsApp भी ब्लॉक, मेटा ने जताई नाराज़गी; पुतिन सरकार ने चेताया— कानून न माने तो बाहर

रूस ने डिजिटल सुरक्षा और स्वदेशी ऐप को बढ़ावा देने के तहत व्हाट्सएप पर कार्रवाई शुरू की है। सरकार ने कानूनों का पालन अनिवार्य बताया है और सर्विस रजिस्ट्री से हटाया है। करीब 10 करोड़ यूजर्स को 'MAX' ऐप पर लाने की तैयारी है। मेटा ने पाबंदियों पर चिंता जताई है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस ने अपने डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और स्थानीय प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत व्हाट्सएप पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार (11 फरवरी 2026) को सामने आई जानकारी के अनुसार, रूसी अधिकारियों ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य देश के करीब 10 करोड़ यूजर्स को रूस के स्वदेशी ऐप 'MAX' की ओर स्थानांतरित करना बताया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यदि व्हाट्सएप को रूस में अपना संचालन जारी रखना है, तो उसे देश के कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मेटा (व्हाट्सएप की मूल कंपनी) यदि रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत और नियमों के अनुपालन के लिए तैयार होती है, तभी किसी संभावित समझौते की गुंजाइश बन सकती है। रूस की संचार निगरानी एजेंसी रोसकोमनादजोर ने भी व्हाट्सएप को अपनी आधिकारिक सर्विस रजिस्ट्री से हटा दिया है। इसे सरकार की ओर से कड़ा संकेत माना जा रहा है कि विदेशी डिजिटल कंपनियों को देश के नियमों के अनुसार काम करना होगा। रूसी अधिकारियों का आरोप है कि कई विदेशी टेक कंपनियां स्थानीय कानूनों का पालन करने और आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम रूस की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने डिजिटल इकोसिस्टम को अधिक आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के साथ बढ़े तनाव और प्रतिबंधों के चलते रूस लगातार विदेशी तकनीकी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में सरकार घरेलू ऐप और प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रही है। रूसी प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का दावा है कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर डेटा नियंत्रण और निगरानी सीमित होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्थानीय कानूनों के तहत डेटा स्टोरेज और साझा करने के नियमों का पालन अनिवार्य किया जा रहा है। व्हाट्सएप की ओर से अभी तक औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वह रूस में अपने यूजर्स को जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। मेटा के मुताबिक, नई पाबंदियों और प्रशासनिक कार्रवाई से उसकी सेवाओं के संचालन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। कंपनी का रुख यह है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार उपलब्ध कराती है, जो यूजर्स की गोपनीयता के लिए जरूरी है। रूस में पहले ही इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ऐसे में व्हाट्सएप पर संभावित रोक को उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यदि पूर्ण प्रतिबंध लागू होता है, तो यह रूस के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप देश में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। तकनीकी जानकारों का मानना है कि यदि यूजर्स को स्वदेशी ऐप 'MAX' पर स्थानांतरित किया जाता है, तो यह रूस की डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि, यह भी देखना होगा कि क्या नया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं और भरोसा प्रदान कर पाएगा।

फिलहाल स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि मेटा और रूसी सरकार के बीच बातचीत होती है, तो किसी समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कानूनों के पालन को लेकर सहमति नहीं बनती, तो रूस में व्हाट्सएप का भविष्य अधर में लटक सकता है।

बांग्लादेश चुनाव में हिंसा: जमात से झड़प में BNP नेता की मौत, पोलिंग बूथ पर बमबारी; बच्ची समेत 3 घायल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए गुरुवार (12 फरवरी 2026) को मतदान जारी है, इस बीच हिंसा की खबरें सामने आई हैं। गोपालगंज और मुंशीगंज में मतदान केंद्रों के बाहर देसी बम फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं खुलना में जमात-ए-इस्लामी के साथ झड़प में BNP नेता की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के गोपालगंज सदर इलाके में पोलिंग बूथ के बाहर हुए बम धमाके में दो अंसार जवान (अर्द्धसैनिक बल) और एक 14 साल की लड़की घायल हो गई। वहीं मुंशीगंज-3 में धमाके के बाद कुछ समय के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा, खुलना में जमात-ए-इस्लामी और BNP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान BNP नेता मोहिबुज्जमान कोच्चि की मौत हो गई। BNP का आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया, जबकि जमात का दावा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। यह चुनाव साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हो रहे हैं, जो देश के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रही हैं। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात-ए-इस्लामी के बीच है।

2000 साल पहले भारत-मिस्र के बीच था गहरा व्यापारिक रिश्ता: कब्रों में तमिल-संस्कृत लिपियों में मिले व्यापारियों के नाम,

अहमदाबाद विमान हादसा: लंदन अखबार का चौंकाने वाला दावा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एअर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। लंदन के अखबार 'द इंडिपेंडेंट' की एअर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक एअर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को अतिरिक्त मुआवजे के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख की अंतिम राशि देकर समझौते की पेशकश कर रही है। कुछ मामलों में यह 20 लाख रुपए तक है। परिवारों को यह शर्त माननी होगी कि वे भविष्य में हादसे से जुड़ा दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त करेंगे। यह छूट किसी भी देश या कोर्ट में लागू रहेगी। एअर इंडिया के इस प्रस्ताव का 130 पीड़ितों के परिवारों की लीगल टीम ने विरोध किया है। उसका कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई है। जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। ऐसे में केस का अधिकार छोड़ने को कहना अनुचित है। कुछ घायल परिवारों का इलाज भी अभी जारी है। इस मामले में एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहे हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती अंतरिम राशि देने के बाद हमने यह तय किया है कि हर परिवार को दी जाने वाली आखिरी रकम सही और कानून के हिसाब से हो। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को केंद्र से विमान हादसे की जांच के 'प्रोसिजरल प्रोटोकॉल' की रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने बताया कि

एएआईबी की जांच अंतिम चरण में है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने एनजीओ सेफ्टी मैटर्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गंभीर एक्सीडेंट के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जरूरत होती है, न एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) की जांच की। इस पर बेंच ने कहा कि AAIB की जांच का नतीजा देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जरूरत होगी या नहीं। इस पर भूषण ने कहा कि 8 हजार से ज्यादा पायलट कह रहे हैं कि बोइंग 787 सेफ नहीं है और इसे ग्राउंड कर देना चाहिए। AAIB जांच टीम में 5 सदस्य डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से हैं। इस पर केंद्र और DGCA की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रशांत भूषण को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका खुद भूषण की अगुआई में कमेटी बनाना है।' अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

दिल्ली रेड फोर्ट अटैक में जैश का हाथ, UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दक्षिण एशिया में आतंकवाद से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की 37वीं रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) को 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले से जोड़ा है, जिसमें कथित तौर पर 15 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, एक सदस्य देश ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले, 8 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर ने संगठन के लिए एक अलग महिला शाखा, जमात-उल-मुमिनात के गठन की घोषणा की थी। हालांकि यह नई शाखा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इस पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। रिपोर्ट में जैश-ए-तैबा की मौजूदा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच मतभेदों पर भी प्रकाश डाला गया है; एक देश का कहना है कि संगठन अभी भी सक्रिय है, जबकि दूसरा देश दावा करता है कि यह "निष्क्रिय" हो गया है। वहीं, पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद जैश-ए-तैबा और लश्कर-ए-तैबा दोनों ही अब सक्रिय नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले का भी जिक्र है, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला प्रतिरोध मोर्चा द्वारा किया गया था, जिसे लश्कर-ए-तैबा का सहयोगी संगठन माना जाता है। 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही हुंडई आई20 में हुए भीषण विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई। विस्फोट में कई अन्य लोग घायल हो गए और आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, जिससे इलाके में व्यापक क्षति हुई। प्रारंभिक जांच में इस घटना का संबंध फरीदाबाद में हाल ही में उजागर हुए एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा गया है। अधिकारियों ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है और हमले के लिए जिम्मेदार माने जा रहे नेटवर्क की पहचान और उसे खत्म करने के लिए व्यापक जांच कर रहे हैं।

मजदूरों और किसानों की देशव्यापी हड़ताल से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय श्रमिक संगठनों और किसान समूहों के आह्वान पर आज देशभर में भारत बंद के तहत व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर और किसान हितों के खिलाफ तथा बड़ी कंपनियों के पक्ष में हैं। इसी के विरोध में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने यह राष्ट्रव्यापी कदम उठाया है जिसे कई किसान संगठनों, छात्र समूहों और युवा संगठनों का भी समर्थन मिला है। आज हो रही हड़ताल के दौरान उठ रही मांगों में मुख्य जोर चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, नए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने पर है। साथ ही मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए अधिक धन और मजबूत प्रावधान की मांग भी उठाई जा रही है। श्रमिक संगठनों ने जरूरी सामान, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने की भी मांग रखी है। हड़ताल के कारण कई जगह जनजीवन पर असर देखा गया। बैंकिंग, बीमा, डाक, परिवहन, खनन, गैस पाइपलाइन और बिजली जैसे क्षेत्रों में आंशिक बाधा की आशंका पहले ही जताई गई थी। हालांकि अस्पताल, आपात सेवाएं, निजी कार्यालय, मेट्रो सेवा और जरूरी आपूर्ति सेवाएं चालू हैं ताकि आम लोगों को बहुत अधिक कठिनाई न हो। केरल में हड़ताल का व्यापक असर दिखा है। राज्य में सरकारी बसें और अधिकतर निजी बसें सड़कों से गायब रहीं, जिससे कार्यालयों में उपस्थिति कम रही। राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर कहा था कि बिना अनुमति अनुपस्थिति रहने पर उस दिन का वेतन काटा जा सकता है। फिर भी परिवहन सेवा ठप रहने से कई कर्मचारी ड्यूटी तक नहीं पहुंच सके। ऑटो यूनियन ने भी सेवा नहीं देने की घोषणा की। कोच्चि मेट्रो और ऑनलाइन टैक्सी सेवा चालू रहने से कुछ राहत मिली। शबरिमला में पूजा के लिए जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रख कर कुछ विशेष बसें चलाने की बात कही गई। तमिलनाडु और केरल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा पूरी तरह रुकी रही। कन्याकुमारी जिले से केरल जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। केरल की राज्य बसें वडसेरी बस अड्डे से नहीं चलीं, जबकि तमिलनाडु की बसें केवल सीमा तक कालियाकाविलई तक चलीं। सीमा पार सेवा बंद रहने से रोज आना जाना करने वाले लोग रास्ते में फंसे रहे। ओडिशा में कई ट्रेड यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया।

संपादक की कलम से

किसान भारत की आत्मा हैं। वे सिर्फ अन्न पैदा नहीं करते बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार भी हैं। कृषि क्षेत्र देश की GDP में लगभग 18-20 प्रतिशत का योगदान देता है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसानों की जिंदगी केवल खेतों तक सीमित नहीं है; यह संघर्ष, परिश्रम और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।भारत में किसान केवल पुरुष नहीं हैं। महिला किसान भी कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। वे खेतों में मेहनत करने के साथ-साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभालती हैं। मौसम की अनिश्चितता, फसल के लिए पर्याप्त पानी और बीज की गुणवत्ता जैसी समस्याएं उनके रोजमर्रा के संघर्ष का हिस्सा हैं। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार तक पहुँच, ऋण और सरकार की नीतियों का प्रभाव भी सीधे इनके जीवन पर पड़ता है। हाल के वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या इस कठिनाई को दर्शाती है। इसके बावजूद, किसान अपने खेतों में काम करते रहते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के बिना भारतीय कृषि की कल्पना अधूरी है। यही कारण है कि महिला किसान को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि किसान के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी दी जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा योजनाएं, किसान कल्याण योजनाएं और महिला किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही, उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजार तक पहुंच प्रदान करना भी आवश्यक है। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण विकास भी सुनिश्चित होगा। किसान केवल खेती के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे देश की सामाजिक और आर्थिक धारा के मुख्य स्तंभ हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष के बिना भारत की आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की कल्पना असंभव है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन्हें केवल सम्मान दें, बल्कि उनके जीवन और काम की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं। कुल मिलाकर, किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके योगदान को समझना और उन्हें सशक्त बनाना हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यही किसान का सम्मान और उनकी मेहनत का सही मूल्य है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का दिल्ली दौरा:

पीएम मोदी और अमित शाह से की महत्वपूर्ण बैठक, एनसीपी के भविष्य पर चर्चा की संभावना

महाराष्ट्र की नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह उनका पहला राष्ट्रीय दौरा है। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के संगठनात्मक संतुलन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। मर्जर या विलय का कोई निर्णय नहीं लिया गया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात की। अपने पति और एनसीपी नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद यह उनके लिए पहला दिल्ली दौरा है। इस दौरे को केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी के भविष्य की रणनीति के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुनेत्रा पवार के साथ इस दौरे में उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार, साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे भी मौजूद थे। दिल्ली में हुई बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और सुनेत्रा पवार को उनके नए उत्तरदायित्व के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण समर्थन की प्रतिबद्धता जताई।राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर थी कि इस दौरे के दौरान एनसीपी (अजित पवार गुट) और शरद पवार गुट के बीच किसी तरह के विलीनीकरण या मर्जर पर बातचीत हो सकती है। हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि इस दौरे का एजेंडा किसी भी तरह के मर्जर या विलय पर चर्चा नहीं था। एनसीपी (अजित पवार गुट) के कई विधायक इस प्रकार के विलीनीकरण का कड़ा विरोध कर रहे हैं और पार्टी ने इसे फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं किया है। अजित पवार के गुट के नेताओं ने किसी भी तरह के कंसोलिडेशन या मर्जर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वर्तमान में पार्टी की प्राथमिकता सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में संगठन को स्थिर करना और आगामी राजनीतिक रणनीति तैयार करना है। दौरे के दौरान एनसीपी और एनसीपी (शरद पवार गुट) के मर्जर पर कोई चर्चा नहीं हुई, और इसे किसी भी बैठक के एजेंडे में भी शामिल नहीं किया गया। राज्यसभा की स्थिति और पार्टी नेतृत्वसुनेत्रा पवार ने अभी तक राज्यसभा से अपना इस्तीफा नहीं दिया है और फिलहाल वह अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में "वेट एंड वॉच" की रणनीति अपना रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह रणनीति उन्हें आगामी पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक समय देती है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर सुनेत्रा पवार को नेशनल प्रेसिडेंट बनाने पर व्यापक सहमति है। इसे औपचारिक रूप देने के लिए फरवरी के अंत तक नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। इसके लिए मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सदस्य शामिल होंगे। साथ ही खबर है कि पार्टी पार्थ पवार को राज्यसभा में भेजने के मुद्दे पर सकारात्मक है। इससे पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और सुनेत्रा पवार के नए उत्तरदायित्वों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

सुनेत्रा पवार का यह दौरा केवल शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं था। इसे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में एनसीपी की भूमिका और भविष्य की रणनीति के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के साथ हुई बैठकों में अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के संगठनात्मक बदलाव, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी की दिशा और संभावित राजनीतिक गठबंधनों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए एनसीपी के नेताओं को आश्वासन दिया। इस प्रकार का समर्थन न केवल सुनेत्रा पवार के व्यक्तिगत राजनीतिक कदमों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होगा।

लोकसभा में राहुल गांधी पर BJP का हमला,

निशिकांत दुबे ने सदस्यता रद्द करने की उठाई बड़ी मांग

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने एएनआई को बताया कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने अपने प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव गांधी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम एक वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं, एक महाशक्ति का युग समाप्त हो गया है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। फिर भी, इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, आपने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। जब अमेरिका कहता है कि हम किसी विशेष देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी रूप से नियंत्रित की जा रही है, ऊर्जा का ही हमारे खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूं कि आपने भारत के हितों से समझौता किया है।

राहुल गांधी का केंद्र पर जोरदार हमला:

मजदूर और किसानों की अनसुनी आवाज़, श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नई श्रम संहिताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण देश के मजदूरों और किसानों का भविष्य अंधकार में है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वे जनता की आवाज़ सुनेंगे या उनके ऊपर किसी बाहरी "ग्रिप" का प्रभाव इतना मजबूत है कि आम लोगों की चिंताओं को अनसुना किया जा रहा है।राहुल गांधी ने विशेष रूप से चार श्रम संहिताओं का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मजदूरों और किसानों के भविष्य को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी "ग्रिप" की पकड़ बहुत मजबूत है।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी।'' उनके अनुसार, किसानों को आशंका है कि अमेरिका के साथ किए गए व्यापार समझौते उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, तब उनकी आवाज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया।'' उन्होंने पुनः सवाल किया कि क्या मोदी जी अब मजदूरों और किसानों की सुनेंगे या उन पर किसी "ग्रिप" की पकड़ बहुत मजबूत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, ''मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।''केंद्र सरकार ने कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नई श्रम संहिताएं तैयार की हैं। ये हैं:वेतन संहिता – मजदूरों के वेतन और भत्तों से जुड़े नियम।औद्योगिक संबंध संहिता – संगठन और यूनियनों के बीच संबंधों का निर्धारण। सामाजिक सुरक्षा संहिता – बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित।व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता – कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। सरकार का कहना है कि ये सुधार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाएंगे और निवेश को आकर्षित करेंगे। हालांकि, विपक्ष और कई ट्रेड यूनियन इसे मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने और पूंजीपतियों के पक्ष में कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इन संहिताओं से मजदूर वर्ग और किसान समुदाय की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

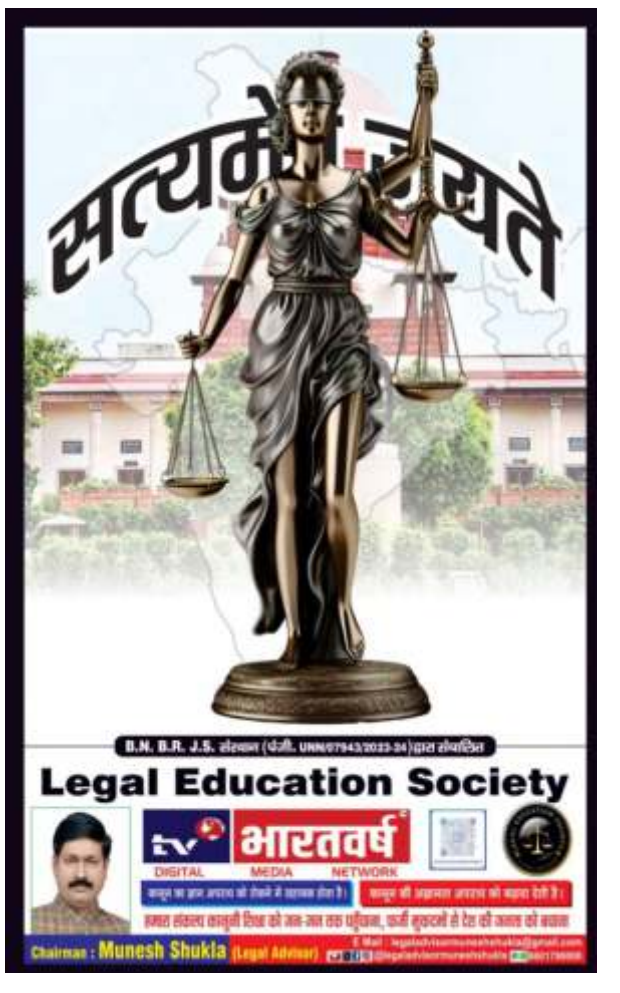

सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर:
UPSC ने IES और ISS पदों के लिए भर्ती जारी की

UPSC ने IES और ISS परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों का चयन केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 3 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. UPSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. IES के लिए 16 पद निर्धारित किए गए हैं. वहीं ISS के लिए 28 पद तय किए गए हैं.यह दोनों सेवाएं केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित सेवाओं में शामिल हैं. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए.सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जायेगी. IES पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है.ISS पद के लिए उम्मीदवार के पास सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी या एप्लाइड सांख्यिकी विषय में बैचलर डिग्री के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है. UPSC द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये तय किया गया है. महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , और दिव्यांग ,उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है. UPSC उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में गलती सुधारने का मौका भी देगा. आयोग करेक्शन विंडो खोलेगा, जिसमें उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपनी जानकारी में सुधार कर सकेंगे.यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है.इसलिए उम्मीदवार फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरें.

ICC इवेंट का सबसे बड़ा ओपनिंग डे इतिहास रचा: ओपनिंग डे पर टूटे व्यूअरशिप के सभी रिकॉर्ड

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 ने व्यूअरशिप के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत और श्रीलंका में शुरू हुए टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल 18.3 बिलियन मिनट बार देखा गया, जो ICC इवेंट के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग व्यूअरशिप बन गई है। अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले गए 2024 टी-20 वर्ल्ड कप की तुलना में ओपनिंग डे की व्युअरशिप में 59% का इजाफा हुआ है। दर्शकों की रीच में भी उछाल देखने को मिला है। जियो-हॉटस्टार पर पहले दिन 10.1 करोड़ (101.9 मिलियन) लोगों ने मैच देखा, जो 2024 वर्ल्ड कप के मुकाबले 81% ज्यादा है। भारत-अमेरिका मैच ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की। भारत ने 2024 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। इस मैच के मुकाबले भारत-अमेरिका मैच की टीवी रेटिंग 41% और डीजिटल रीच 98% बढ़ी है। ICC के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अनुराग दहिया ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जबरदस्त रही है। जियो-हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप से टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर व्यूअरशिप में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन 18.3 बिलियन मिनट की कंजम्प्शन दिखाती है कि क्रिकेट के लिए लोगों में कितना जुनून है। जियोस्टार के स्पोर्ट्स CEO ईशान चटर्जी ने कहा कि 9 भाषाओं में कमेंट्री और शानदार मैचों ने पहले दिन ही फैंस को जोड़े रखा। उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ती व्यूअरशिप से ब्रांड पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स को भी जबरदस्त फायदा मिल रहा है।

इटली की टी-20 वर्ल्ड कप में पहली जीत

इटली की टीम को टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत मिल गई है। टीम पहली बार ही टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। पहले मैच में स्कॉटलैंड से हारने के बाद उसने दूसरे मुकाबले में नेपाल के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर इटली ने 10 विकेट से नेपाल को हराया। टी20 रैंकिंग में नेपाल की टीम 16वें तो इटली 26वें नंबर पर है। पहले खेलते हुए नेपाल की पारी सिर्फ 123 रनों पर सिमट गई। इटली के लिए दो भाई जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का सलामी बल्लेबाज करने उतरे और उन्होंने टीम को 13वें ओवर में बिना विकेट खोए जीत दिला दी। इटली के लिए दो भाई जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने आते ही अटैक कर दिया और नेपाल को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में करन केसी के खिलाफ एंथोनी ने छक्का लगाया। तीसरे ओवर में जस्टिन ने एक छक्का और दो चौके मारे। पावरप्ले में ही दोनों ने टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया।

रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार:
लक्ष्य देश के लिए ट्रॉफी जीतना

श्रीलंका की शानदार जीत:
ओमान को 105 रन से हराया,

श्रीलंकाई टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने गुरुवार के पहले मैच में ओमान को 105 रन से हराया। यह श्रीलंका की टी-20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप-बी के इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाबी पारी में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। मोहम्मद नदीम ने 53 रन की पारी खेली। वसीम अली ने 27 रन बनाए। दुष्मंथा चमीरा और महीश तीक्षणा ने 2-2 विकेट झटके। दुनिथ वेल्लालागे, दुशन हेमंथा और कमिंडु मेंडिस को 1-1 विकेट मिला। विनायक शुक्ला और सुफियान महमूद रन आउट हुए। इससे पहले, श्रीलंका की ओर से कुसल मेंडिस (61), पवन रत्नायके (60) और दासुन शनाका (50) ने अर्धशतक लगाए। शनाका ने 19 बॉल पर फिफ्टी लगाई। वे श्रीलंका के लिए टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। ओमान के लिए जितेन रामानंदी ने 2 विकेट लिए। जय ओडेदरा और सुफियान महमूद को 1-1 विकेट मिला। कुसल मेंडिस रन आउट हुए।

रोजर फेडरर के लिए फैंस का जुनून:
4500 टिकट सिर्फ 2 मिनट में सॉल्ड आउट

रोजर फेडरर ने भले ही टेनिस को अलविदा कह दिया हो लेकिन उनका जादू अब भी प्रशंसकों पर सर चढ़कर बोलता है जिसकी बानगी यहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ़ फेम में शामिल करने के समारोह के टिकटों की भारी मांग में देखने में मिली। फेडरर से जुड़े इस समारोह के सभी टिकट दो मिनट में बिक गए। आयोजकों ने आउटडोर पार्टी के लिए अलग से अतिरिक्त टिकट जारी किए जो हाथों हाथ बिक गए। आखिर में आयोजकों को कहना पड़ा कि उनकी क्षमता सीमित है और वह अधिक टिकट जारी नहीं कर सकते हैं। आयोजक हॉल ऑफ़ फेम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक स्थल होने के कारण हमारी क्षमता सीमित है।'' हॉल ने कहा कि उसे पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी फेडरर को लेकर कितना उत्साह होगा। इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को 29 अगस्त को प्रसारक मैरी कैरिलो के साथ हॉल ऑफ़ फेम में शामिल किया जाएगा। न्यूपोर्ट स्थित इस प्रतिष्ठित हॉल में होने वाले मुख्य समारोह के लिए पहले से उपलब्ध 900 टिकटों के अलावा हॉल अपने 3,600 सीटों वाले स्टेडियम को एक विशेष कार्यक्रम के लिए खोलेगा। इसके बावजूद हॉल की प्रवक्ता मेगन एर्ब्स ने कहा कि 4,500 टिकट दो मिनट के भीतर ही बिक गए।

बना रहा है भव्य 'गोल्ड डिस्ट्रिक्ट', 1000 से ज्यादा शोरूम होंगे एक साथ

दुबई में बनेगी सोने की सड़क

दुबई में दुनिया की पहली 'गोल्ड स्ट्रीट' बनाई जा रही है, जिसकी सड़क के निर्माण में सोने का उपयोग होगा। यह दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगी, जहां 1,000 से अधिक खुदरा विक्रेता और विशाल बुलियन बाजार एक ही स्थान पर मौजूद होंगे.

दुबई में बन रहा है एक गोल्ड डिस्ट्रिक्ट, यहीं बनेगी सोने की सड़क (Photo - Pixabay)

दुबई की टैक्स फ्री लाइफस्टाइल और गोल्ड सूक की वजह से यहां की सड़कों को भी सोने का बना हुआ मना जाता रहा है. अब दुबई से जुड़ी ये कहवत सच होने जा रही है. क्योंकि दुबई में जल्द ही 'गोल्ड डिस्ट्रिक्ट' बनाया जाएगा और इसका मुख्य आकर्षण 'गोल्ड स्ट्रीट' होगा. यहां की सड़क सोने की बनी होगी. यह दुनिया की पहली 'गोल्ड स्ट्रीट' होगी. दुबई में दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के निर्माण की घोषणा की गई है. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट शहर के मौजूदा गोल्ड सूक का ही नया रूप होगा. इस क्षेत्र में लगभग 1,000 खुदरा विक्रेता हैं जो सोना और आभूषण बेचते हैं. ऐसे में गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के अहम हिस्से के रूप में दुनिया की पहली "गोल्ड स्ट्रीट" बनाने की योजना भी योजना है. यहां सोने की खुदरा बिक्री, बुलियन व्यापार और थोक गतिविधियों को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाएगा. गल्फ न्यूज के मुताबिक, डेवलपर्स ने बताया कि दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होने के नाते इस गोल्ड स्ट्रीट की सड़कों के निर्माण में सोने का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका उद्देश्य गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में एक आकर्षण बनना है. ⊙

बीमार पड़ते ही इंजीनियर ने छोड़ी गूगल की नौकरी

जिंदगी में हर इंसान की तलाश क्या होती है. जल्द से जल्द पैसा कमाना, खुद को एक इनसेक्योर जोन से सेक्योर जोन में ले जाना, लेकिन असल जिंदगी की प्राथमिकता क्या है. रेस में सबसे आगे जाना या फिर जिंदगी की बुनियादी जरूरत वो सेहत है,जिसे दरकिनार कर दिया जाता है. अमेरिका में रहने वाली टिया ली की कहानी भी इन्हीं दो चीजों के इर्द-गिर्द घूमती है. ⊙

भारतीय महिला का वीडियो वायरल

'ऑस्ट्रेलिया आकर ट्रैप में फंस गई'

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी को मज़ाकिया अंदाज़ में एक ट्रैप बताया है. वजह यह है कि वहां की साफ हवा, शांत माहौल और बेहतर काम-जीवन संतुलन ने उसकी सोच ही बदल दी. महिला ने इंस्टाग्राम पर एक हल्का-फुल्का लेकिन सटीक व्यंग्य वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल दिखाती हैं. वीडियो में वह कहती हैं कि किसी ने उन्हें पहले नहीं बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जाना

ऐसा ट्रैप होगा, जहां ज़िंदगी इतनी सुकून भरी हो जाएगी. वीडियो में वह बताती हैं कि वह अब रोज़ सुबह 6 बजे उठती हैं, जिम जाती हैं और अपने पार्टनर के साथ 10 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं- वो भी सिर्फ मज़े के लिए. वह हंसते हुए कहती हैं कि अब उन्हें काम पर जाने की प्रेरणा मिलती है और जो ज़िंदगी भारत में कभी सपना लगती थी. ⊙

दुबई के शासक से डरकर भागीं राजकुमारी हाया

क्यों गांव में रहने को मजबूर है जॉर्डन की प्रिंसेस?

दुबई के गर्म रेगिस्तानऔर विशाल संगमरमर के महलों से हजारों मील दूर, अरब की एक राजकुमारी ने ब्रिटेन के एक छोटे से गांव को अपना घर बना लिया है. यहां वह पुरानी हवेली को अपना आशियाना बना रही हैं. राजकुमारी अपने पति से डरकर दुबई से भागी थीं. उनके पति दुबई के शासक हैं. अब उन्होंने आलीशान महलों से दूर एक खंडहर को अपने रहने लायक बनाने का काम शुरू किया है. यहां बात हो रही है हाया बिन्त हुसैन की, जिन्होंने 2019 में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से तलाक के बाद ब्रिटेन में रहने का फैसला किया. इस कपल का तलाक अब तक के सबसे बड़े तलाक समझौते में से एक हैं. जिसमें राजकुमारी को 554 मिलियन पाउंड मिले थे. इस प्रिंसेस ने दुबई के अपने

संगमरमर के आलीशान महलों वाली जीवनशैली को छोड़कर वेल्स के ग्रामीण इलाके के एक जर्जर हवेली को अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया.

जॉर्डन के राजा की बेटी, 51 साल की इस राजकुमारी ने वेल्स के सुदूर गांव पॉविस में स्थित ईस्ट कंट्री के एक होटल पर 3.5 मिलियन पाउंड खर्च किए हैं. कहा जा रहा है कि वह इस होटल का रेनोवेशन कराने में लाखों पाउंड और खर्च कर रही हैं, ताकि यह उस स्तर का हो सके जिसकी उम्मीद बेहद अमीर शाही परिवार से की जाती है.स्थानीय लोगों ने द सन को बताया कि राजकुमारी का यह नया आशियाना पुराना होने के बावजूद हाई सिक्योरिटी वाला ठिकाना है जो ज़्यादा समय तक खंडहर नहीं रहेगा, क्योंकि बिना किसी खर्च की परवाह किए इसका रेनोवेशन शुरू हो गया है.

हाया बिंत हुसैन ने अप्रैल 2019 में, अपने पति से खुद को 'जान का खतरा' बताकर दुबई छोड़कर भाग आई थीं. वह उनसे अलग हो गई, क्योंकि उनके पति को एक ब्रिटिश बॉडीगार्ड के साथ उनके रिश्ते पर संदेह होने लगा था और इसी वजह से उनका वैवाहिक जीवन टूट गया. तलाक के निपटारे के दौरान, उच्च न्यायालय के एक जज ने कहा कि दुबई के शासक, जो अब 76 वर्ष के हैं. ⊙

भुवन बाम की नई फिल्म 'कुकू की कुंडली' की शूटिंग शुरू

डिजिटल दुनिया से पहचान बनाने वाले भुवन बाम अब बड़े पर्दे पर किस्मत आजमाने जा रहे हैं. यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स से करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले भुवन ने जिस सफर की शुरुआत छोटे-छोटे वीडियो से की थी, वो अब बॉलीवुड तक पहुंच चुका है. उनकी पहली फिल्म 'कुकू की कुंडली' की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है और इसी के साथ भुवन बाम का बॉलीवुड डेब्यू ऑफिशियल हो गया है. उनके फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भुवन बाम सोशल मीडिया का तो जाना माना चेहरा हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को खूब एंटरटेन किया है. पर अब भुवन बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है. फिल्म 'कुकू की कुंडली' भुवन का बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है, इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो बॉलीवुड में बड़े और सफल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है. ऐसे बैनर के साथ डेब्यू करना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है. फिल्म का डायरेक्शन करण शर्मा कर रहे हैं, 'कुकू की कुंडली' की कहानी को हल्के-फुल्के अंदाज और एंटरटेनिंग ट्विस्ट के साथ पेश किए जाने की तैयारी है, जिसमें भुवन एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ की कई खास लोकेशंस चुनी गई हैं. शहर के अलग-अलग हिस्सों में फिल्म की टीम काम कर रही है. बताया जा रहा है कि फिल्म का शेड्यूल करीब एक महीने तक चलेगा. इसके अलावा जानकारी मिली है कि फिल्म के कुछ हिस्सा कानपुर में भी शूट किया जाएगा. भुवन के साथ इस फिल्म में वामिका गब्बी, मनोज पाहवा और गीता अग्रवाल शर्मा जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आएंगे, जिससे फिल्म की स्टारकास्ट और मजबूत हो गई है. भुवन बाम इससे पहले वेब सीरीज ढिंढोरा और ताजा खबर में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुके हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, लेकिन बड़े पर्दे की चुनौती अलग होती है. यही वजह है कि उनका ये कदम खास माना जा रहा है. एक कंटेंट क्रिएटर से मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर बनने का सफर भुवन के लिए बहुत खास होने वाला है.

लखनऊ में भारत-अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर डीएम से मिलने की मांग

लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने भारत–अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। "मेरा खेत – मेरा अधिकार" के नारे लगाते हुए उन्होंने डीएम से मिलने और केंद्र सरकार तक अपना ज्ञापन पहुंचाने की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

भारत–अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के कई सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी "मेरा खेत – मेरा अधिकार" के नारे लगा रहे थे और डीएम कार्यालय के सामने धरना देकर बैठ गए। उनका मुख्य उद्देश्य जिलाधिकारी से मिलकर केंद्र सरकार तक अपनी समस्याओं और विरोध का ज्ञापन पहुंचाना था।प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि वे अपने गांवों से बहुत दूर निकलकर राजधानी आए हैं ताकि अपनी आवाज सुनाई जा सके। किसानों ने जिलाधिकारी विशाख जी. के कार्यालय के सामने काफी देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन डीएम ने सीधे तौर पर उन्हें मिलने से रोक दिया। किसानों ने कहा, "हम लोग गांव इतनी दूर से आए हैं और डीएम साहब कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा ज्ञापन लेने के बाद ही हम लौटेंगे।"भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि भारत–अमेरिका कृषि समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि इस समझौते के तहत किसानों की फसलें और घरेलू बाजार प्रभावित होंगे और विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। इसी कारण उन्होंने केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया।धरने के दौरान किसानों ने मुख्य रूप से मंडियों में समर्थन मूल्य, फसल की उचित कीमत, और बड़े कॉर्पोरेटों के हस्तक्षेप से बचाव के मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि इस बार उनका आंदोलन केवल प्रतीकात्मक धरना नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप ले सकता है।स्थानीय प्रशासन ने किसानों के धरने को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए तैयार रहा। हालांकि, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसानों ने किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की। प्रशासन ने किसानों से संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों का कहना था कि वे केवल जिलाधिकारी से मिलकर ही ज्ञापन देना चाहते हैं।किसानों ने बताया कि उनका ज्ञापन केंद्र सरकार तक उनके हक और हितों की रक्षा के लिए भेजा जाएगा। ज्ञापन में मुख्य रूप से कृषि समझौते की खामियों, संभावित नुकसान और छोटे किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल अपनी आवाज उठाना है और सरकार से मांग है कि किसानों के हितों को नजरअंदाज न किया जाए।इस प्रदर्शन के दौरान कई स्थानीय किसान भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कृषि संकट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों और विदेशी समझौतों के चलते ग्रामीण किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। उनका मानना है कि यदि किसानों की आवाज को गंभीरता से नहीं सुना गया तो इसका असर केवल खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के खाद्य सुरक्षा ढांचे पर पड़ेगा।कुल मिलाकर, यह धरना–प्रदर्शन किसानों की नाराजगी और केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी चेतावनी का प्रतीक था। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाला, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इस प्रकार, लखनऊ में भारत–अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में किसानों का यह प्रदर्शन उनके हक और अधिकार की लड़ाई के रूप में उभरा।

लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक का कहर: साइकिल सवार को कुचला

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी के सैरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना सैरपुर स्थित छठा मील चौराहे पर दोपहर करीब 2:45 बजे की है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, साइकिल सवार चौराहे से गुजर रहा था तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही साइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान ट्रक का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसका सिर बुरी तरह फट गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए।घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सैरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रक चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चालक की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चौराहे पर अक्सर भारी वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर हंगामा:

करोड़ों की FD घोटाले के आरोप में ग्राहकों ने शटर गिरवाया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का शटर ग्राहकों ने गिरा दिया। गुरुवार सुबह 25 से अधिक खाताधारक बैंक पहुंचे और अपनी जमा राशि वापस न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वे शटर बाहर से बंद कर वहीं पर बैठ गए। 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक का काम बंद है। ज्यादातर ग्राहक बाहर बैठकर नारेबाजी की। दरअसल, इस ब्रांच में शिवा राव नाम के बैंक मित्र ने लोगों की FD कराकर उसे खाते में चढ़ाया ही नहीं था। जब FD मैच्योर की डेट आई तो लोग बैंक पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी कोई FD हुई ही नहीं थी। कई ग्राहकों के खाते से भी रकम गायब थी। सालिकराम पाल ने बताया कि उनकी बेटी कमला का तिलक कार्यक्रम कल होना है, लेकिन बैंक में जमा किए गए 17 लाख 30 हजार रुपए अब तक वापस नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि परिवार बेहद परेशान है और शादी की तैयारियां अधर में लटक गई हैं। खाताधारकों का कहना है कि उनकी जीवन भर की बचत दांव पर लगी है, ऐसे में जब तक रकम वापस नहीं मिलती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सूचना पर पहुंची पारा पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन खाताधारक अपनी मांगों पर डटे रहे। इसी तरह, दोना गांव की कुमकुम ने बताया कि उन्होंने 2024 में बेटी के भविष्य के लिए चार लाख रुपए जमा किए थे, जो अब खाते में नहीं हैं। सलेमपुर पतोरा निवासी सरोजिनी के खाते से जमीन बिक्री के 33.35 लाख रुपए गायब मिले हैं। रामसिंह यादव के खाते से भी लगभग 18.60 लाख रुपए निकाला गया है। न्यू हैदरगंज रोड की रंजना राजपूत, अंजलि, आरती, समित कुमार और विशाल वर्मा सहित कई अन्य खाताधारकों ने भी अपने खातों से दो से चार लाख रुपए तक की रकम गायब होने का आरोप लगाया है। घोटाले के कई पीड़ित अपनी आपबीती सुना रहे हैं। नरोना निवासी अंशु ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए सरकार से मिली पांच लाख रुपए की अनुदान राशि जमा की थी, जिसमें से तीन लाख रुपए उनके खाते से गायब हैं।

सीसीटीवी बंद होना अब बहाना नहीं, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकारा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीधे मुख्य सचिव को कहा है कि रिपोर्ट मांगी जाती है तो बार-बार वही जवाब आता है। बता देते हैं कि तकनीकी खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब थानों की तय कहानी है। अब 23 फरवरी तक में थानों में लगे CCTV कैमरों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। अगर उस दिन जांच रिपोर्ट नहीं पेश हो पाएगी तो आपको खुद ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम में पेश होना पड़ेगा। वहीं पर आपसे पूरा जवाब लिया जाएगा। दरअसल, सुल्तानपुर के याचिकाकर्ता श्याम सुंदर अग्रहरि ने याचिका दाखिल की थी। उनके वकील शिवेंद्र सिंह राठौर ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता एक दिव्यांग व्यक्ति है, जिसे हत्या के प्रयास के एक कथित मामले में कथित तौर पर फर्जी तरीके से फंसाया गया है। याचिका में सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाने में उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से थानों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज मांगे थे, जिसके जवाब में बताया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने कहा कि यह एक ही बहाना बार-बार नहीं चलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई (23 फरवरी) तक जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं होती है, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब भी थानों से सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है, तो एक ही जवाब मिलता है कि कैमरे बंद थे या खराब थे। न्यायालय ने इसे अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज समय पर प्रस्तुत न करने का प्रयास माना और उत्तर प्रदेश पुलिस के इस व्यवहार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करार दिया।

लखनऊ में टैंकर हादसा: मौसी की मौत, भांजा घायल

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के सरोजनी नगर में बुधवार शाम एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 20 साल की युवती किरन की मौत हो गई, जबकि युवक रामसागर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना नादरगंज-अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर नादरगंज तिराहे से करीब 200 मीटर दूर हुई। टैंकर ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिससे रामसागर और किरन बाइक समेत गिर गए। टक्कर के बाद टैंकर दोनों के ऊपर से गुजर गया। वहीं घटना के बाद टैंकर चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, सरोजनी नगर के चिल्लावां गांव निवासी चंद्रशेखर उर्फ कंचन का बेटा रामसागर (19) आलमबाग के जनता इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र है। उसकी मौसी किरन (20) उन्नाव जिले के इब्राहिमपुर से चिल्लावां में अपने बहनोई के घर आ रही थी। हादसे में रामसागर का बायां पैर टूट गया। किरन के पेट के ऊपर से टैंकर का पहिया गुजरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। आनन-फानन में एंबुलेंस से दोनों को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया।

KGMU में 50 दिन में तीसरा यौन शोषण मामला, संस्थान पर फिर उठे सवाल

KGMU में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह 50 दिन में तीसरा केस है। अब पीडियाट्रिक विभाग की एमडी की छात्रा (रेजिडेंट डॉक्टर) ने विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरैसमेंट करने का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए विशाखा भी गठित कर दी गई है। इस बीच आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। KGMU प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि घटना सामने आने के बाद आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग में डॉक्टर की एंट्री करने पर रोक लगा दी गई है। KGMU प्रशासन पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रहा है। दोषी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता डॉक्टर (एमडी छात्रा) ने 11 फरवरी को शिकायत की थी। शिकायत के तुरंत बाद KGMU प्रशासन ने विशाखा कमेटी गठित की। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। विशाखा कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। बाल रोग विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्रता का इल्जाम लगाया है। साथ ही मोबाइल पर संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने परिवारीजनों के साथ केजीएमयू प्रशासन से शिकायत की। शिकायत के आधार पर केजीएमयू प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशाखा कमेटी को मामले की जांच के आदेश दिए। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के आदेश पर विशाखा कमेटी ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। आरोपी एडिशनल प्रोफेसर से पूछताछ की। कमेटी को शुरुआती जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले हैं। लिहाजा केजीएमयू प्रशासन ने एडिशन प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

19 मार्च को रामनगरी में रामोत्सव का शुभारंभ, राष्ट्रपति होंगी उपस्थित

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की धार्मिक–सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या इस वर्ष रामभक्ति और सांस्कृतिक वैभव के बड़े मंच के रूप में तैयार है। राज्य सरकार ने अयोध्या के रामनवमी मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिया है, जिससे इसे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा गया है और देशभर के श्रद्धालुओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। परंपरा के अनुसार रामनवमी मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, लेकिन श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ सप्तमी से ही मेला क्षेत्र में जमा होने लगती है। इस वर्ष मेला औपचारिक रूप से 19 मार्च से शुरू होगा। रामनवमी (नवमी) के दिन रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उत्साह अपने चरम पर रहता है।

अयोध्या प्रशासन और संबंधित विभागों ने भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी तेज कर दी है। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में रामोत्सव की परंपरा को और विस्तारित किया गया है। यह आयोजन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त समन्वय में संपन्न होगा। सूत्रों के अनुसार, 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी और रामोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति राम मंदिर के दूसरे तल पर स्थित "राम नाम मंदिर" में पूजन भी करेंगी। इसी दिन भगवान राम के विशेष यंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इस यंत्र की स्थापना कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। स्वर्ण यंत्र पहले कांचीपुरम से अयोध्या लाया गया था और शोभायात्रा के जरिए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती भी यंत्र स्थापना के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रह सकते हैं। राम मंदिर निर्माण से जुड़े करीब 400 श्रमिकों को 19 मार्च से प्रस्तावित सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। समारोह में लगभग 5,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख कारसेवकों के परिजन भी शामिल हो सकते हैं।

विशेष बात यह है कि समारोह के दौरान राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था भी जारी रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, आवास और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालु प्रतिपदा से ही मेला स्थल पर पहुंचना शुरू कर देंगे, जबकि सप्तमी से भीड़ का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने चेकपोस्ट, सीसीटीवी कैमरा और अन्य निगरानी प्रबंध किए हैं। यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष मार्ग बनाए गए हैं, और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुफ्त परिवहन व्यवस्था भी की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भजन-कीर्तन और रामलीला प्रस्तुतियों का आयोजन भी मेला स्थल पर किया जाएगा। इस दौरान अयोध्या को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए नगर निकाय और स्थानीय प्रशासन ने सजावट एवं साफ-सफाई के कार्यों को तेज किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य रामनवमी मेले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और इसे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित करना है। इससे न केवल देशभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जाएगा, बल्कि अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी और बढ़ेगा। रामोत्सव के माध्यम से अयोध्या को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है।

HDFC बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह भदौरिया ने कहा, मुझे बदनाम किया

टीवी भारतवर्ष कानपुर

कानपुर में HDFC बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह भदौरिया ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आस्था ने कहा कि वह इस स्थिति में मानसिक तनाव महसूस कर रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे सुसाइड तक कर लें।आस्था ने आरोप लगाया कि दूसरी कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी ने सीधे उनके चरित्र पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा, "जब लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो वे महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। मेरे चरित्र से बड़ा दाग और क्या लगाया जा सकता है। ऋतु को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गलती उनके पति की है।"दरअसल, 6 जनवरी को कानपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आस्था सिंह दूसरी कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी और उनके पति से कहती नजर आ रही हैं, "मैं ठाकुर हूं, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी।" वीडियो में गुस्से में आस्था लैपटॉप उठाकर किसी पर हमला करने की कोशिश करती भी दिखाई देती हैं। यह वीडियो 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।वीडियो के वायरल होने के बाद आस्था और ऋतु के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दैनिक भास्कर एप की टीम ने इस पूरे मामले पर आस्था सिंह से बातचीत की।

उन्नाव में ओवर हाइट गेज डीसीएम की टक्कर से टूटा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के हसनगंज-अजगैन-मोहन मार्ग पर नवाई गांव के पास नाले पर लगा ओवर हाइट गेज देर रात एक डीसीएम की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोहे का गेज टूटकर नीचे गिर गया और डीसीएम का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के कारण मार्ग पर कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने डीसीएम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने इस मार्ग पर बढ़ते सड़क हादसों और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से कुछ समय पहले ओवर हाइट गेज स्थापित कराया था। गेज लगने के बाद से भारी और निर्धारित ऊंचाई से अधिक वाहनों का प्रवेश लगभग बंद हो गया था।

महाशिवरात्रि पर काशी-मुंबई का अद्भुत संगम

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक महत्वपूर्ण और विशेष पहल की है। इस बार मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर से भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के लिए फल, फूल और अन्य पूजन सामग्री श्रद्धा के साथ काशी विश्वनाथ धाम भेजी गई। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष प्रसाद और पूजन सामग्री बाबा के दरबार में विधिपूर्वक पहुंचाई गई है, जिससे महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को और भी भव्य और आध्यात्मिक रूप दिया जा सके।विशेष रूप से इस पहल को भगवान श्री गणेश और भगवान महादेव के शाश्वत पिता-पुत्र संबंध की आध्यात्मिक भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। मंदिर न्यास और प्रशासन ने इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है, बल्कि यह देश के प्रमुख तीर्थों के मध्य सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम भी माना जा रहा है।श्री सिद्धिविनायक मंदिर के डिप्टी सीईओ संदीप राठौर ने कहा कि महाशिवरात्रि जैसे महापर्व पर इस तरह की पहल न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव को सशक्त बनाती है, बल्कि देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच सौहार्द और समन्वय को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने इस नवाचार के माध्यम से भगवान श्री गणेश एवं परमपिता महादेव के पावन संबंध को जनमानस के समक्ष प्रतिष्ठित करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का विशेष आभार व्यक्त किया।इतिहास के अनुसार, वर्तमान समय में जिस स्वरूप में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, उसका निर्माण 1780 में कराया गया था। यह कार्य इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होल्कर ने अपने धर्मपरायण दृष्टिकोण से करवाया था। इसके अतिरिक्त, काशी विश्वनाथ मंदिर के दो प्रमुख गुंबदों को महाराजा रणजीत सिंह ने सोने से ढकवाया था, जो आज भी मंदिर की भव्यता और ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाते हैं।विशेष रूप से महादेव की नगरी में स्थित विश्वनाथ शिवलिंग का इतिहास सदियों पुराना है। इसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ के पावन शिवलिंग ने समय-समय पर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा है। अब, महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर से भेजे गए प्रसाद ने इस ऐतिहासिक मंदिर में भक्तों के उत्साह और श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया है।मंदिर न्यास के अधिकारियों ने बताया कि इस बार की पहल के तहत भेजी गई फल, फूल और पूजन सामग्री का वितरण विधिपूर्वक पूजा स्थलों में किया जाएगा, ताकि भक्तगण भी इस धार्मिक आयोजन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल हो सकें। यह पहल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि यह यह दर्शाती है कि देश के प्रमुख तीर्थ स्थल आपस में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं।संदीप राठौर ने कहा, "भगवान श्री गणेश और परमपिता महादेव के पावन संबंध को जनमानस के समक्ष स्थापित करने के लिए यह पहल अत्यंत सार्थक है।" उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक समन्वय से देश में धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को भी बल मिलता है।इस प्रकार, महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई यह विशेष पहल भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बन गई है और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के बीच सहयोग और श्रद्धा की भावना को मजबूती प्रदान कर रही है।

उन्नाव में यूपी बोर्ड परीक्षा, 139 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को इस वर्ष नकल मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस उद्देश्य के लिए जिले में कुल 139 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसमें 6 जोनल, 11 सेक्टर और 122 स्टेटिक मजिस्ट्रेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 122 केंद्र व्यवस्थापक और समान संख्या में अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट को जिले की एक तहसील के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। उनके मार्गदर्शन में सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे। जिले की छह तहसीलों में स्थित कुल 122 परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेगा, जो प्रश्नपत्र वितरण, उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता और परीक्षा कक्ष की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगा। इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। उन्नाव जिले में कुल 71,675 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें हाईस्कूल के 39,508 और इंटरमीडिएट के 32,166 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। ये परीक्षाएं जिले के 122 निर्धारित केंद्रों पर संपन्न कराई जाएंगी। इनमें 10 राजकीय, 50 अशासकीय सहायता प्राप्त और 62 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। जिला प्रशासन ने छह परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया है, जहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जिले की छह तहसीलों में कुल 59 सहायता प्राप्त, 41 राजकीय और 314 वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। प्रशासन ने बताया कि बोर्ड परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर बाद होगी। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विद्यालयों को प्राप्त हो चुके हैं और उनका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, उड़नदस्तों की सक्रियता और सख्त जांच व्यवस्था के माध्यम से किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक पूरी सावधानी के साथ तैनात रहेंगे। स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा कक्ष में प्रश्नपत्र वितरण से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रह तक की निगरानी करेंगे। वहीं, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक होगा और वे कई केंद्रों की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

जिले में इस वर्ष आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई है। सभी संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार, उन्नाव में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा के दौरान अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ निभाएं।

उन्नाव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के मौरावां थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मोती खेड़ा हिलौली गांव की है, जहां बुधवार शाम यह दुखद वाकया सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंकित यादव (27) पुत्र राजा राम के रूप में हुई है। वह अपने दो भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। परिजनों के अनुसार, अंकित बुधवार शाम अपने कमरे में गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। जब परिजनों ने दरवाजा खटखटाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर परिजनों ने अंकित को फंदे से लटका पाया। उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारा और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौरावां पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रिश्तेदारों और ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि अंकित किसी युवती से फोन पर बातचीत करता था। बताया जा रहा है कि उस युवती की शादी 13 फरवरी को तय थी। परिजनों ने भी पुलिस को बताया है कि घटना से पहले अंकित की उस युवती से फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था पर बहस तेज,

विधान परिषद से सपा का वॉक आउट

यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था पर सपा और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। रागिनी सोनकर ने पुलिस और कस्टोडियल डेथ के मामलों को उठाया, जबकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुधार और आंकड़ों के साथ जवाब दिया। सपा का वॉकआउट दिखाता है कि विपक्ष कानून व्यवस्था पर गंभीर है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश बजट सत्र का आज चौथा दिन है और विधान परिषद तथा विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस ने नया मोड़ ले लिया। आज सदन में सवाल-जवाब और बहस के दौरान सपा के सदस्य वॉक आउट कर गए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दसवें बजट का जिक्र करते हुए पिछले नौ वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।विधानसभा में आज सवाल-जवाब के दौरान सपा विधायक रागिनी सोनकर और मंत्री नंद गोपाल नंदी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। रागिनी सोनकर ने कहा कि राज्य में हालात चिंताजनक हैं और पुलिस प्रशासन लगातार न्यायपालिका की फटकार का सामना कर रहा है। उन्होंने प्रयागराज में मकर संक्रांति की शाम चार खटीक समाज के युवकों की हत्या का मामला उठाया। उनका आरोप था कि ये सभी बच्चे नग्न होकर खनन तालाब में नहा रहे थे और पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी मौत हो गई। रागिनी ने कहा कि यूपी कस्टोडियल डेथ में टॉप पर पहुंच गया है और सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने की जरूरत है।इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में राज्य में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों की तुलना में यूपी बेहतर स्थिति में है। खन्ना ने प्रयागराज में डूबने से हुई चार बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि परिवारों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है और आवास भी प्रदान किया गया है।विधानसभा में खेल मंत्रालय पर भी चर्चा हुई। सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर अच्छा स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, उसी तरह से एक खिलाड़ी अच्छा खेल मंत्री भी हो सकता है। उन्होंने वर्तमान खेल मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कभी गिल्ली-डंडा भी नहीं खेला।इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य का दसवां बजट पेश किया था। उन्होंने बजट वर्ष 2026-27 की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में यूपी का बजट तीन गुना बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस अवधि में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और प्रदेश का कर्ज भी घटाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए बजट में प्रस्तावित की गई है। योगी ने यह भी गौरवपूर्वक बताया कि किसी मुख्यमंत्री को दसवां बजट पेश करने का अवसर अब तक नहीं मिला।बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।वहीं, विपक्ष ने बजट में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। रागिनी सोनकर ने सदन में कहा कि इस सरकार के कारण महिला, युवा, बेरोजगार और किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रयागराज के मामले जैसी घटनाएं दर्शाती हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था संकट में है।सपा के सदस्यों का वॉकआउट इस बात का संकेत है कि विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मामलों पर गंभीरता से जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है। विधानसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने कहा कि राज्य में कस्टोडियल डेथ, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार को इसका समाधान करना होगा।इस पूरे सत्र में यह स्पष्ट हुआ कि यूपी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास और बजट की उपलब्धियों का जोर देकर उल्लेख किया, जबकि विपक्ष ने इन मुद्दों पर सवाल उठाकर सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की।कुल मिलाकर, यूपी विधानसभा में आज का सत्र कानून व्यवस्था, बजट और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। विपक्ष ने सरकार पर हमला किया, वहीं सरकार ने अपने सुधार और विकास का ब्यौरा पेश किया। यह सत्र राज्य की राजनीतिक सक्रियता और जनता की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर गंभीर बहस का प्रतीक बन गया है।

मुजफ्फरनगर एनकाउंटर: वर्दी में लूटपाट करने वाला अमजद कार्बाइन फायरिंग में ढेर

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया। गुरुवार तड़के साढ़े तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अपने गांव आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस टीम ने बदमाश को कई बार सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की ओर से कुल 20 राउंड फायरिंग की गई। इसमें एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष अत्री बाल-बाल बच गए। उनके बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी। दरोगा संदीप चौधरी और सिपाही अशफाक के हाथ में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाब देते हुए 4 राउंड फायरिंग की। इस दौरान अजमद को गोली लगी। वह गिर पड़ा। पुलिस उसे उठाकर गाड़ी तक ले गई, फिर बुढ़ाना सीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मुठभेड़ बुढ़ाना थाना क्षेत्र में हुई। 40 साल का बदमाश अजमद मुजफ्फरनगर के ही शाहपुर का रहने वाला था। उस पर यूपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में कुल 40 मुकदमे दर्ज थे। 2021 में राजस्थान के चुरू में मुथूट फाइनेंस से 5 किलो सोना लूटा था। पुलिस की वर्दी में ही वह अक्सर वारदात को अंजाम देता था। उसने हाल ही में बुढ़ाना थाने में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इसी मामले में उसकी तलाश कर रही थी।

हिस्ट्रीशीटर के साथ भागने वाली सिपाही की लव स्टोरी

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

मेरठ में शादी के दिन महिला सिपाही अचानक हिस्ट्रीशीटर के साथ चली गई। परिवार के लोगों ने समझा कि अपहरण हो गया। लेकिन बाद में मामला 12 साल पुरानी लव स्टोरी का निकला। मेरठ की महिला सिपाही संध्या भारद्वाज के कथित अपहरण मामले ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। जांच में सामने आया कि वह अपनी शादी वाले दिन खुद ही एक हिस्ट्रीशीटर युवक के साथ चली गई थी। मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं, बल्कि 12 साल पुराने प्रेम संबंध का निकला। जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में 8 फरवरी को शादी की खुशियां थीं। घर में ढोलक बज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थीं। परिवार बारात की तैयारी में जुटा था। संध्या भारद्वाज की शादी अलीगढ़ में तैनात एक सिपाही से तय हुई थी। लेकिन शादी से ठीक पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ। जिसने पूरे इलाके को चर्चा में ला दिया। 7 फरवरी की देर रात करीब 2 बजे गांव में हिस्ट्रीशीटर अंकित चौहान बाइक लेकर पहुंचा। उसने संध्या को फोन किया। थोड़ी ही देर में संध्या घर से बाहर आई। परिवार के लोग भी पीछे-पीछे पहुंच गए। वहां कहासुनी हुई। अंकित ने विरोध जताया कि जब दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं। तो शादी कहीं और क्यों की जा रही है। इसके बाद संध्या खुद उसकी बाइक पर बैठ गई। और दोनों वहां से चले गए। परिवार ने इसे अपहरण मानते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीमाओं पर घेराबंदी कर दी। मामला महिला सिपाही से जुड़ा होने के कारण तेजी से कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ ही घंटों में घटनाक्रम बदल गया। संध्या मवाना थाने पहुंची और बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से अंकित के साथ गई थी। दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। लेकिन हालात बिगड़ने पर ऐसा नहीं हो सका।

MLC आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में कहा- दुकानदारों को सुरक्षित जगह पर बसाया जाए, दालमंडी है गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

वाराणसी के हाकिम मोहम्मद जाफर मार्ग (दालमंडी) में चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। इस समय 30 से अधिक मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अभी तक 35 मकानों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। इधर लगातार अब दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर आवाज उठ रही है। इसी क्रम में वाराणसी स्नातक क्षेत्र से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में दालमंडी का मुद्दा उठाया और दुकानदारों के हक और उन्हें विस्थापित करने की बात कही। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विधान परिषद में दालमंडी का मुद्दा उठाया। दालमंडी में चल रहे चौड़ीकरण के कार्य को उन्होंने सही ठहराया। लेकिन उन्होंने दुकानदारों की बात की और उन्हें कहीं अन्य जगह बसाने की बात की। उन्होंने कहा- यहां सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और कौमी एकता का यह मिसाल है। लेकिन उसके बावजूद इसे तोड़ा जा रहा है जो की गलत है क्योंकि यहां के दुकानदारों को कहीं और बसाया नहीं जा रहा है। जो की गलत और नियम विरुद्ध है। विधान परिषद में बोलते हुए एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा - हाकिम मोहम्मद जफर मार्ग जिसे दालमंडी के नाम से जाना जाता है। पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। सभी जाति, धर्म के लोगों का यहां व्यापार चलता है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी दुकानें इस दालमंडी में हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब का उदहारण है वह दालमंडी में ही देखने को मिलता है। होली, दीवाली,ईद, बकरीद सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका पुराना नाम हाकिम मोहम्मद जफर मार्ग है सरकार को